

[दि सिक््युरिटी लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2014 का हिन्दी अनुवाद]

प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2014

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992,
प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956
और निक्षेपागार अधिनियम, 1996
का संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 है ।
- 5 (2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 5 के खंड (ii), धारा 6, से धारा 16, धारा 25 से धारा 33, धारा 36 और धारा 41 से धारा 48 को छोड़कर यह 18 जुलाई, 2013 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।
- (3) इस अधिनियम की धारा 5 के खंड (ii), धारा 16, धारा 33, धारा 36 और धारा 48 के उपबंध 28 मार्च, 2014 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(4) इस अधिनियम की धारा 6 से धारा 15, धारा 25 से धारा 32 और धारा 41 से धारा 47 के उपबंध, उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

अध्याय 2

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 का संशोधन

धारा 11 का संशोधन।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (जिसे इस अध्याय में इसके 5 1992 का 15 पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 में,—

(i) उपधारा (2) में,—

(क) खंड (झक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(झक) किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित किसी बैंक या किसी अन्य प्राधिकारी या बोर्ड या निगम 10 सहित किसी व्यक्ति से ऐसी सूचना और अभिलेख मंगाना, जो बोर्ड की राय में ऐसी प्रतिभूतियों में किसी संव्यवहार की बाबत बोर्ड द्वारा किसी अन्वेषण या जांच के लिए सुसंगत होगा ;” ;

(ख) खंड (झक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और उसको 6 मार्च, 1998 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :— 15

“(झख) प्रतिभूति विधियों के संबंध में अतिक्रमणों के निवारण या उनका पता लगाने से संबंधित मामलों में, इस संबंध में तत्समय प्रवृत्त किन्हीं अन्य विधियों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड के समान कृत्य करने वाले अन्य प्राधिकारियों से, चाहे वे भारत में हों या भारत के बाहर, सूचना मंगाना या उनको सूचना देना : 20

परंतु बोर्ड, भारत से बाहर किसी प्राधिकारी को किसी सूचना को देने के प्रयोजन के लिए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे प्राधिकरण के साथ कोई ठहराव या करार या बात तय कर सकेगा ;” ;

(ii) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 25

“(5) यथास्थिति, इस अधिनियम की धारा 11ख या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 12क या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19 के 1956 का 42 अधीन जारी निदेश के अनुसरण में प्रत्यर्पित रकम को, बोर्ड द्वारा स्थापित विनिधानकर्ता 1996 का 22 संरक्षण और शिक्षा निधि में जमा किया जाएगा और ऐसी रकम का, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार बोर्ड द्वारा उपयोग किया जाएगा ।”। 30

धारा 11कक का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 11कक में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) “उपधारा (2)”, शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात् “या उपधारा (2क)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 35

“परन्तु किसी स्कीम या ठहराव के अधीन निधियों का पूल किया जाना, जो बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है या उपधारा (3) के अधीन समाविष्ट नहीं है, जिसमें एक सौ करोड़ रुपए या अधिक की समग्र रकम अंतर्वलित है, सामूहिक विनिधान स्कीम होना समझा जाएगा ।” ;

(ii) उपधारा (2) के आरंभिक भाग में, “कंपनी” शब्द के स्थान पर “व्यक्ति” शब्द रखा जाएगा ;

(iii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

5 “(2क) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार विनिर्दिष्ट की जाने वाली शर्तों का समाधान करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई या प्रस्थापित की गई कोई स्कीम या ठहराव।” ;

(iv) उपधारा (3) में,—

(क) “उपधारा (2)” शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात् “या उपधारा (2क)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

10 (ख) खंड (viii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ix) ऐसी अन्य स्कीम या ठहराव जिसको केन्द्रीय सरकार, बोर्ड के परामर्श से अधिसूचित करे,”।

15 4. मूल अधिनियम की धारा 11ख में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, धारा 11ख का संशोधन।

20 “स्पष्टीकरण— शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के अधीन निदेशों को जारी करने की शक्ति में, किसी ऐसे व्यक्ति को, निदेश करने की शक्ति सम्मिलित होगी और सदैव उसका सम्मिलित होना समझा जाएगा, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उल्लंघन में, किसी संयवहार या क्रियाकलाप में लगकर, ऐसे उल्लंघन से कमाए गए सदोष अभिलाभ या टाली गई हानि के समान रकम का प्रत्यर्पण करने के लिए लाभ कमाता है या हानि को टालता है।”।

5. मूल अधिनियम की धारा 11ग में,—

धारा 11ग का संशोधन।

25 (i) उपधारा (8) में, “अधिकारिता रखने वाले प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को” शब्दों के स्थान पर “मुंबई में ऐसे नामनिर्दिष्ट न्यायालय के मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

30 “(8क) प्राधिकृत अधिकारी, किसी अधिकारी या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या दोनों की सेवाओं की, उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उसकी सहायता करने के लिए अपेक्षा कर सकेगा और ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करना प्रत्येक ऐसे अधिकारी का कर्तव्य होगा।”;

(iii) उपधारा (9) में दोनों स्थानों पर आने वाले “मजिस्ट्रेट” शब्द के स्थान पर “नामनिर्दिष्ट न्यायालय के मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश” शब्द रखे जाएंगे;

(iv) उपधारा (10) में “मजिस्ट्रेट” शब्द के स्थान पर “नामनिर्दिष्ट न्यायालय के मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश” शब्द रखे जाएंगे।

35 6. मूल अधिनियम की धारा 15क के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में, “ऐसी शास्ति का, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए होगी या एक करोड़ रुपए होगी, इनमें से जो भी कम हो, दायी होगा” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी शास्ति का, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो 40 सकेगी, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 15क का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 15छ में, "पच्चीस करोड़ रुपए होगी या ऐसे आंतरिक व्यापार से प्राप्त लाभ की रकम का तीन गुना होगी, इनमें से जो भी अधिक हो" शब्दों के स्थान पर, "दस लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो पच्चीस करोड़ रुपए तक की हो सकेगी या ऐसे आंतरिक व्यापार से प्राप्त लाभ की रकम का तीन गुना हो सकेगी, इनमें से जो भी अधिक हो," शब्द रखे जाएंगे। धारा 15छ का संशोधन।
- 5 13. मूल अधिनियम की धारा 15ज में, "पच्चीस करोड़ रुपए होगी या ऐसी असफलता से प्राप्त लाभ की रकम का तीन गुना होगी, इनमें से जो भी अधिक हो" शब्दों के स्थान पर, "दस लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो पच्चीस करोड़ रुपए तक की हो सकेगी या ऐसी असफलता से प्राप्त लाभ की रकम का तीन गुना हो सकेगी, इनमें से जो भी अधिक हो," शब्द रखे जाएंगे। धारा 15ज का संशोधन।
- 10 14. मूल अधिनियम की धारा 15जक में, "पच्चीस करोड़ रुपए होगी या ऐसी प्रथाओं से प्राप्त लाभ की रकम के तीन गुना होगी, इनमें से जो भी अधिक हो" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो पच्चीस करोड़ रुपए तक की हो सकेगी या ऐसी प्रथाओं से प्राप्त लाभ की रकम के तीन गुना हो सकेगी, इनमें से जो भी अधिक हो," शब्द रखे जाएंगे। धारा 15जक का संशोधन।
- 15 15. मूल अधिनियम की धारा 15जख में, "ऐसी शास्ति के लिए, जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति का, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे। धारा 15जख का संशोधन।
16. मूल अधिनियम की धारा 15झ में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:- धारा 15झ का संशोधन।
- “ (3) बोर्ड, इस धारा के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अभिलेख को मंगा सकेगा और परीक्षा कर सकेगा तथा यदि यह विचार करता है कि न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश उस विस्तार तक गलत है, यह प्रतिभूति बाजार के हितों में नहीं है तो वह ऐसी जांच करने या करवाने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, शास्ति की मात्रा में वृद्धि करते हुए, यदि मामले की परिस्थितियां उसको न्यायोचित ठहराती हैं, आदेश पारित कर सकेगा:
- परन्तु ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक संबद्ध व्यक्ति को मामले में सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है :
- 25 परन्तु यह और कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश की तारीख से तीन मास की अवधि के अवसान या धारा 15न के अधीन अपील के निपटान के पश्चात्, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, लागू नहीं होगी।”।
- 30 17. मूल अधिनियम की धारा 15जक के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और उसको 20 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :- नई धारा 15जक का अंतःस्थापन।
- 35 “15जख. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कोई कार्यवाही धारा 11, धारा 11ख, धारा 11घ, धारा 12 की उपधारा (3) या धारा 15झ के अधीन आरंभ की गई है या आरंभ की जा सकेगी, अभिकथित व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई या आरंभ की जाने वाली कार्यवाहियों के निपटारे का प्रस्ताव करने के लिए बोर्ड को लिखित में आवेदन फाइल कर सकेगा। प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा।
- (2) बोर्ड, व्यक्तियों की प्रकृति, गंभीरता और समाघात पर विचार करने के पश्चात्, व्यक्तियों द्वारा ऐसी राशि के संदाय पर या ऐसे अन्य निबंधनों पर, जो बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार अवधारित किए जाएं, निपटारे के लिए प्रस्ताव से सहमत हो सकेगा।
- (3) इस धारा के अधीन निपटारा कार्यवाहियों को, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संचालित किया जाएगा।
- (4) इस धारा के अधीन, यथास्थिति, बोर्ड या न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध धारा 15न के अधीन कोई अपील नहीं होगी।”।

- धारा 15न का संशोधन।
धारा 26 का संशोधन।
नई धारा 26क, धारा 26ख, धारा 26ग, धारा 26घ और धारा 26ङ, का अंतःस्थापन।
विशेष न्यायालयों की स्थापना किया जाना।
18. मूल अधिनियम की धारा 15न की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।
19. मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।
20. मूल अधिनियम की धारा 26 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
- “26क. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का शीघ्र विचारण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा, उतने विशेष न्यायालयों को, जितने आवश्यक हों, स्थापित या नामनिर्दिष्ट कर सकेगी।
- (2) विशेष न्यायालय, ऐसे एकल न्यायाधीश से गठित होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, जिसकी अधिकारिता के भीतर नियुक्त किया जाने वाला न्यायाधीश कार्यरत है, नियुक्त किया जाएगा।
- (3) कोई व्यक्ति, किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक वह ऐसी नियुक्ति से ठीक पूर्व, यथास्थिति, कोई सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश के पद को धारण नहीं करता है।
- 26ख. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व या ऐसे प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् किए गए इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का, ऐसे क्षेत्र के लिए, जिसमें अपराध किया गया है, स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा या जहां ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय हैं, उनमें से ऐसे किसी एक द्वारा, जो इस निमित्त संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, संज्ञान लिया जाएगा और विचारण किया जाएगा।
- 26ग. उच्च न्यायालय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 29 और अध्याय 30 द्वारा, उच्च न्यायालय को प्रदत्त सभी शक्तियों का, जहां तक लागू हो सके, उसी प्रकार प्रयोग कर सकेगा मानो उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों का विचारण करने वाला कोई सेशन न्यायालय था।
- 26घ. (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय का, सेशन न्यायालय होना समझा जाएगा तथा विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति का, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खंड (प) के अर्थात्तर्गत लोक अभियोजक होना समझा जाएगा।
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति को, सात वर्ष से अन्यून के लिए अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय में होना चाहिए या विधि के विशेष ज्ञान की अपेक्षा करते हुए संघ या राज्य के अधीन सात वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए किसी पद को धारण करना चाहिए।
- 26ङ. इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का, जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है, जब तक विशेष न्यायालय स्थापित न किया जाए, तब तक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाले सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और विचारण किया जाएगा :

विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराध।

अपील और पुनरीक्षण।

विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में संहिता का लागू होना।

संक्रमणकालीन उपबंध।

5

10

1974 का 2

15

20

1974 का 2

25

1974 का 2

30

35

1974 का 2

1974 का 2

परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, इस धारा के अधीन सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए गए किसी मामले या मामलों के वर्ग को अंतरित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 407 के अधीन उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगी ।”।

5 21. मूल अधिनियम की धारा 28 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 28क का अंतःस्थापन ।

10 '28क. (1) यदि कोई व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति के संदाय में असफल रहता है या धन के प्रतिदाय के लिए बोर्ड के किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है या धारा 11ख के अधीन जारी प्रत्यर्पण आदेश के निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है या बोर्ड को देय किन्हीं फीसों का संदाय करने में असफल रहता है तो वसूली अधिकारी, व्यक्ति से देय रकम विनिर्दिष्ट करते हुए, विनिर्दिष्ट प्ररूप में अपने लेख में एक कथन (ऐसे कथन को इस अध्याय में इसके पश्चात् प्रमाण-पत्र कहा गया है) तैयार कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति से प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम को निम्नलिखित एक या अधिक पद्धतियों से वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगा, अर्थात् :—

रकमों की वसूली ।

15 (क) व्यक्ति की जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय ;

(ख) व्यक्ति के बैंक खातों की कुर्की ;

(ग) व्यक्ति की स्थावर संपत्ति की कुर्की और विक्रय ;

(घ) व्यक्ति की गिरफ्तारी और कारागार में उसका निरोध ;

20 (ङ) व्यक्ति की जंगम और स्थावर संपत्तियों के प्रबंध के लिए प्रापक की नियुक्ति,

1961 का 43

और इस प्रयोजन के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 220 से धारा 227, धारा 228क, धारा 229, धारा 232, दूसरी और तीसरी अनुसूचियों तथा समय-समय पर प्रवृत्त आय-कर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के उपबंध, जहां तक हो सके ऐसे आवश्यक उपांतरणों के साथ लागू हो सकेंगे मानो उक्त उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियम, इस अधिनियम के उपबंध थे और इस अधिनियम के अधीन देय रकम के प्रति, आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन आय-कर के स्थान पर निर्देश हैं ।

30 **स्पष्टीकरण 1**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन में, ऐसी कोई संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन सम्मिलित हैं, जो ऐसी तारीख को या उसके पश्चात्, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, अंतरित किए गए हैं, जब प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट कोई रकम, व्यक्ति द्वारा पर्याप्त प्रतिफल से भिन्न उसके पति या पत्नी या अप्राप्तवय बालक या पुत्र की पत्नी या पुत्र के अप्राप्तवय बालक को देय हो चुकी थी और जो पूर्वोक्त किन्हीं व्यक्तियों द्वारा धारित की गई है या उनके नाम पर है और जहां तक उसके अप्राप्तवय बालक या उसके पुत्र के अप्राप्तवय बालक को इस प्रकार अंतरित जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन का संबंध है

35 वहां उसका, यथास्थिति, ऐसे अप्राप्तवय बालक या पुत्र के अप्राप्तवय बालक के व्यस्क होने की तारीख के पश्चात् भी इस अधिनियम के अधीन व्यक्ति से देय किसी रकम की वसूली करने के लिए व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन में सम्मिलित होना बना रहेगा ।

1961 का 43

40

स्पष्टीकरण 2—आय-कर अधिनियम, 1961 की दूसरी और तीसरी अनुसूचियों और आय-कर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के उपबंधों के अधीन निर्धारित के प्रति किसी निर्देश का, प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के बारे में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके प्रतिनिर्देश है ।

स्पष्टीकरण 3—आय—कर अधिनियम, 1961 के अध्याय 17घ और दूसरी अनुसूची में अपील के प्रति किसी निर्देश का, इस अधिनियम की धारा 15न के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण के समक्ष अपील के बारे में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके प्रति निर्देश है। 1961 का 43

(2) वसूली अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय स्थानीय जिला प्रशासन की सहायता प्राप्त करने के लिए सशक्त होगा। 5

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, धारा 11ख के अधीन बोर्ड द्वारा जारी किसी निदेश के अननुपालन के अनुसरण में उपधारा (1) के अधीन किसी वसूली अधिकारी द्वारा रकमों की वसूली की, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी अन्य दावे पर अग्रता होगी।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए “वसूली अधिकारी” 10 पद से बोर्ड का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसको लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाए।’।

धारा 30 का संशोधन।

22. मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(गक) धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन जमा की गई रकम का उपयोग 15 किया जाना ;

(गख) धारा 11कक की उपधारा (2क) के अधीन सामूहिक विनिधान स्कीम से संबंधित अन्य शर्तों का पूरा किया जाना ;” ;

(ii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(घक) धारा 15अख की उपधारा (2) के अधीन कार्यवाहियों के निपटारे के लिए बोर्ड द्वारा अवधारित निबंधन और उपधारा (3) के अधीन निपटारा कार्यवाहियों के संचालन के लिए प्रक्रिया ; 20

(घख) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसको विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा या जिसके संबंध में विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।” । 25

नई धारा 34क का अंतःस्थापन।

23. मूल अधिनियम की धारा 34 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण।

“34क. बोर्ड के समरूप कृत्य करने वाले अन्य प्राधिकरणों से, चाहे वे भारत में हैं या भारत के बाहर हैं, जानकारी मांगने या उनको जानकारी देने के संबंध में और प्रशासनिक तथा सिविल कार्यवाहियों के निपटान के संबंध में मूल अधिनियम के अधीन किया गया या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्य या कोई बात, सभी प्रयोजनों के लिए उतनी ही विधिमान्य और प्रभावी रही 30 समझी जाएगी मानो मूल अधिनियम में किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त थे।”।

अध्याय 3

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 का संशोधन

धारा 12क का संशोधन।

24. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 12क में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 35

1956 का 42

“स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के अधीन निदेशों को जारी करने की शक्ति में, किसी ऐसे व्यक्ति को, निदेश करने की शक्ति सम्मिलित होगी और सदैव उसका सम्मिलित होना समझा जाएगा, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उल्लंघन में, किसी संव्यवहार या 40

क्रियाकलाप में लगकर, ऐसे उल्लंघन से कमाए गए सदोष अभिलाभ या टाली गई हानि के समान रकम का प्रत्यर्पण करने के लिए लाभ कमाता है या हानि को टालता है।”।

25. मूल अधिनियम की धारा 23क के खंड (क) और खंड (ख) में, “ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे। धारा 23क का संशोधन।
26. मूल अधिनियम की धारा 23ख में, “ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा” शब्दों के स्थान पर “ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे। धारा 23ख का संशोधन।
27. मूल अधिनियम की धारा 23ग में, “ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे। धारा 23ग का संशोधन।
28. मूल अधिनियम की धारा 23घ में, “एक करोड़ रुपए से अनधिक की शास्ति के लिए दायी होगा” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे। धारा 23घ का संशोधन।
29. मूल अधिनियम की धारा 23ङ में, “पच्चीस करोड़ रुपए से अनधिक की शास्ति के लिए दायी होगा” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी शास्ति के लिए, जो पांच लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो पच्चीस करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे। धारा 23ङ का संशोधन।
30. मूल अधिनियम की धारा 23च में, “पच्चीस करोड़ रुपए से अनधिक की शास्ति के लिए दायी होगा” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी शास्ति के लिए, जो पांच लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो पच्चीस करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे। धारा 23च का संशोधन।
31. मूल अधिनियम की धारा 23छ में, “पच्चीस करोड़ रुपए से अनधिक की शास्ति के लिए दायी होगा” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी शास्ति के लिए, जो पांच लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो पच्चीस करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे। धारा 23छ का संशोधन।
32. मूल अधिनियम की धारा 23ज में, “ऐसी शास्ति के लिए, जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे। धारा 23ज का संशोधन।
33. मूल अधिनियम की धारा 23झ में उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— धारा 23झ का संशोधन।

“(3) बोर्ड, इस धारा के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अभिलेख को मंगा सकेगा और परीक्षा कर सकेगा तथा यदि यह विचार करता है कि न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश उस

विस्तार तक गलत है, यह प्रतिभूति बाजार के हितों में नहीं है तो वह ऐसी जांच करने या करवाने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, शास्ति की मात्रा में वृद्धि करते हुए, यदि मामले की परिस्थितियां उसको न्यायोचित ठहराती हैं, आदेश पारित कर सकेगा :

परन्तु ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक संबद्ध व्यक्ति को मामले में सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है : 5

परन्तु यह और कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश की तारीख से तीन मास की अवधि के अवसान या धारा 15न के अधीन अपील के निपटान के पश्चात्, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, लागू नहीं होगी।”।

नई धारा 23जक का अंतःस्थापन ।

34. मूल अधिनियम की धारा 23ज के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और उसको 20 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :— 10

प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा ।

“23जक. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कोई कार्यवाही धारा 12क या धारा 23झ के अधीन आरंभ की गई है या आरंभ की जा सकेगी, अभिकथित व्यक्तिक्रमों के लिए आरंभ की गई या आरंभ की जाने वाली कार्यवाहियों के निपटारे का प्रस्ताव करने के लिए बोर्ड को लिखित में आवेदन फाइल कर सकेगा । 15

(2) बोर्ड, व्यक्तिक्रमों की प्रकृति, गंभीरता और समाघात पर विचार करने के पश्चात्, व्यक्तिक्रमी द्वारा ऐसी राशि के संदाय पर या ऐसे अन्य निबंधनों पर, जो बोर्ड द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार अवधारित किए जाएं, निपटारे के लिए प्रस्ताव से सहमत हो सकेगा । 1992 का 15

(3) इस धारा के अधीन निपटारे के प्रयोजन के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रक्रिया लागू होगी । 20 1992 का 15

(4) इस धारा के अधीन, यथास्थिति, बोर्ड या न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध धारा 23ठ के अधीन कोई अपील नहीं होगी ।”।

नई धारा 23जख का अंतःस्थापन ।

35. इस प्रकार अंतःस्थापित की गई, मूल अधिनियम की धारा 23जक के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 25

रकमों की वसूली ।

‘23जख. (1) यदि कोई व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति के संदाय में असफल रहता है या धारा 12क के अधीन जारी प्रत्यर्पण आदेश के निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है या बोर्ड को देय किन्हीं फीसों का संदाय करने में असफल रहता है तो वसूली अधिकारी, व्यक्ति से देय रकम विनिर्दिष्ट करते हुए, विनिर्दिष्ट प्ररूप में अपने लेख में एक कथन (ऐसे कथन को इस अध्याय में इसके पश्चात् प्रमाणपत्र कहा गया है) तैयार कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति से प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम को निम्नलिखित एक या अधिक पद्धतियों से वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगा, अर्थात् :— 30

(क) व्यक्ति की जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय ;

(ख) व्यक्ति के बैंक खातों की कुर्की ;

(ग) व्यक्ति की स्थावर संपत्ति की कुर्की और विक्रय ; 35

(घ) व्यक्ति की गिरफ्तारी और कारागार में उसका निरोध ;

(ङ) व्यक्ति की जंगम और स्थावर संपत्तियों के प्रबंध के लिए प्रापक की नियुक्ति,

और इस प्रयोजन के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 220 से धारा 227, धारा 228क, धारा 229, धारा 232, दूसरी और तीसरी अनुसूचियों तथा समय-समय पर प्रवृत्त 40

1961 का 43

आय-कर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के उपबंध, जहां तक हो सके ऐसे आवश्यक उपांतरणों के साथ लागू हो सकेंगे मानो उक्त उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियम, इस अधिनियम के उपबंध थे और इस अधिनियम के अधीन देय रकम के प्रति, आय-कर अधिनियम 1961 के अधीन आयकर के स्थान पर निर्देश हैं ।

1961 का 43

5 **स्पष्टीकरण 1**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन में, ऐसी कोई संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन सम्मिलित हैं, जो ऐसी तारीख को या उसके पश्चात्, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, अंतरित किए गए हैं, जब प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट कोई रकम, व्यक्ति द्वारा पर्याप्त प्रतिफल से भिन्न उसके पति या पत्नी या अप्राप्तवय बालक या पुत्र की पत्नी या पुत्र के अप्राप्तवय बालक को देय हो चुकी थी और जो पूर्वोक्त किन्हीं व्यक्तियों द्वारा धारित की गई है या उनके नाम पर है और जहां तक उसके अप्राप्तवय बालक या उसके पुत्र के अप्राप्तवय बालक को इस प्रकार अंतरित जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन का संबंध है वहां उसका, यथास्थिति, ऐसे अप्राप्तवय बालक या पुत्र के अप्राप्तवय बालक के व्यस्क होने की तारीख के पश्चात् भी इस अधिनियम के अधीन व्यक्ति से देय किसी रकम की वसूली करने के लिए व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन में सम्मिलित होना बना रहेगा ।

15

1961 का 43

स्पष्टीकरण 2—आय-कर अधिनियम, 1961 की दूसरी और तीसरी अनुसूचियों और आय-कर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के उपबंधों के अधीन निर्धारित के प्रति किसी निर्देश का, प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के बारे में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके प्रतिनिर्देश है ।

20

1961 का 43

स्पष्टीकरण 3—आय-कर अधिनियम, 1961 के अध्याय 17घ और दूसरी अनुसूची में अपील के प्रति किसी निर्देश का, इस अधिनियम की धारा 23ठ के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण के समक्ष अपील के बारे में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके प्रति निर्देश है ।

25

(2) वसूली अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय स्थानीय जिला प्रशासन की सहायता प्राप्त करने के लिए सशक्त होगा ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, धारा 12क के अधीन बोर्ड द्वारा जारी किसी निर्देश के अननुपालन के अनुसरण में उपधारा (1) के अधीन किसी वसूली अधिकारी द्वारा रकमों की वसूली की, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी अन्य दावे पर अग्रता होगी ।

30

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए “वसूली अधिकारी” पद से बोर्ड का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसको लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाए ।’।

35 **36.** मूल अधिनियम की धारा 23ठ की उपधारा (1) के पश्चात् “धारा 4ख” शब्द, अंक और अक्षर धारा 23ठ का संशोधन ।
के पश्चात्, “या धारा 23झ की उपधारा (3)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

37. मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

धारा 26 का संशोधन ।

38. मूल अधिनियम की धारा 26 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

नई धारा 26क, धारा 26ख, धारा 26ग, धारा 26घ और धारा 26ङ का अंतःस्थापन ।

40 “26क. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का शीघ्र विचारण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा, उतने विशेष न्यायालयों को, जितने आवश्यक हों, स्थापित या नामनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

विशेष न्यायालयों की स्थापना किया जाना ।

(2) विशेष न्यायालय, ऐसे एकल न्यायाधीश से गठित होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, जिसकी अधिकारिता के भीतर नियुक्त किया जाने वाला न्यायाधीश कार्यरत है, नियुक्त किया जाएगा ।

(3) कोई व्यक्ति किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक वह ऐसी नियुक्ति से ठीक पूर्व, यथास्थिति, कोई सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश के पद को धारण नहीं करता है ।

विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराध ।

26ख. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व या ऐसे प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् किए गए इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का, ऐसे क्षेत्र के लिए, जिसमें अपराध किया गया है, स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा या जहां ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय हैं, उनमें से ऐसे किसी एक द्वारा, जो इस निमित्त संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, संज्ञान लिया जाएगा और विचारण किया जाएगा ।

अपील और पुनरीक्षण ।

26ग. उच्च न्यायालय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 29 और अध्याय 30 द्वारा, उच्च न्यायालय को प्रदत्त सभी शक्तियों का, जहां तक लागू हो सकें, उसी प्रकार प्रयोग कर सकेगा मानो उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों का विचारण करने वाला कोई सेशन न्यायालय था ।

विशेष न्यायालयों के समक्ष कार्यवाहियों में संहिता का लागू होना ।

26घ. (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय का, सेशन न्यायालय होना समझा जाएगा तथा विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति का, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खंड (प) के अर्थात्गत लोक अभियोजक होना समझा जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति को, सात वर्ष से अन्यून के लिए अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय में होना चाहिए या विधि के विशेष ज्ञान की अपेक्षा करते हुए संघ या राज्य के अधीन सात वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए किसी पद को धारण करना चाहिए ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

26ड. इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का, जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है, जब तक विशेष न्यायालय स्थापित न किया जाए, तब तक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाले सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और विचारण किया जाएगा :

परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, इस धारा के अधीन सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए गए किसी मामले या मामलों के वर्ग को अंतरित करने के लिए संहिता की धारा 407 के अधीन उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगी ।” ।

धारा 31 का संशोधन ।

39. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) में खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(ग) धारा 23अक के उपखंड (2) के अधीन कार्यवाहियों के निपटारे के लिए बोर्ड द्वारा अवधारित निबंधन;

(घ) कोई अन्य विषय जिनको विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या जिनको विनिर्दिष्ट किया जाए या जिनके संबंध में उपबंध, विनियमों द्वारा बनाया जाना है ।” ।

40. मूल अधिनियम की धारा 31 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

नई धारा 32 का अंतःस्थापन।

“32. प्रशासनिक तथा सिविल कार्यवाहियों के निपटान के संबंध में मूल अधिनियम के अधीन किया गया या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्य या कोई बात, सभी प्रयोजनों के लिए विधिमाम्य और प्रभावी समझी जाएगी मानो मूल अधिनियम में किए गए संशोधन सभी तात्विक समर्थों पर प्रवृत्त रही हो।”।

कतिपय अधिनियमों का विधिमाम्यकरण।

अध्याय 4

निक्षेपागार अधिनियम, 1996 का संशोधन

1996 का 22

10 41. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 19 में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 19 का संशोधन।

15 “स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के अधीन निदेशों को जारी करने की शक्ति में, किसी ऐसे व्यक्ति को, निदेश करने की शक्ति सम्मिलित होगी और सदैव उसका सम्मिलित होना समझा जाएगा, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उल्लंघन में, किसी संव्यवहार या क्रियाकलाप में लगकर, ऐसे उल्लंघन से कमाए गए सदोष अभिलाभ या टाली गई हानि के समान रकम का प्रत्यर्पण करने के लिए लाभ कमाता है या हानि को टालता है।”।

20 42. मूल अधिनियम की धारा 19क के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में, “जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 19क का संशोधन।

25 43. मूल अधिनियम की धारा 19ख में, “ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 19ख का संशोधन।

30 44. मूल अधिनियम की धारा 19ग में, “ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 19ग का संशोधन।

35 45. मूल अधिनियम की धारा 19घ में, “ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 19घ का संशोधन।

40 46. मूल अधिनियम की धारा 19ङ में, “ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 19ङ का संशोधन।

- धारा 19च का संशोधन। 47. मूल अधिनियम की धारा 19च में, "ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे। 5
- धारा 19छ का संशोधन। 48. मूल अधिनियम की धारा 19छ में, "ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी," शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी" शब्द रखे जाएंगे।
- धारा 19ज का संशोधन। 49. मूल अधिनियम की धारा 19ज में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :- 10
- “(3) बोर्ड इस धारा के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अभिलेख को मंगा सकेगा और परीक्षा कर सकेगा तथा यदि वह यह विचार करता है कि न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश उस विस्तार तक गलत है कि यह प्रतिभूति बाजार के हितों में नहीं है तो वह ऐसी जांच करने या करवाने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, शास्ति की मात्रा में वृद्धि करते हुए, यदि मामले की परिस्थितियां उसको न्यायोचित ठहराती हैं, आदेश पारित कर सकेगा : 15
- परन्तु ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक संबद्ध व्यक्ति को मामले में सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है :
- परन्तु यह और कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश की तारीख से तीन मास की अवधि के अवसान या धारा 23क के अधीन अपील के निपटान के पश्चात्, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, लागू नहीं होगी।”। 20
- नई धारा 19झक का अंतःस्थापन। 50. मूल अधिनियम की धारा 19झ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और उसको 20 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :-
- प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा। “19झक. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कोई कार्यवाही, यथास्थिति, धारा 19 या धारा 19ज के अधीन आरंभ की गई है या आरंभ की जा सकेगी, अभिकथित व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई या आरंभ की जाने वाली कार्यवाहियों के निपटारे का प्रस्ताव करने के लिए बोर्ड को लिखित में आवेदन फाइल कर सकेगा। 25
- (2) बोर्ड, व्यक्तियों की प्रकृति, गंभीरता और समाघात पर विचार करने के पश्चात्, व्यक्तियों द्वारा ऐसी राशि के संदाय पर या ऐसे अन्य निबंधनों पर, जो बोर्ड द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार अवधारित किए जाएं, निपटारे के लिए प्रस्ताव से सहमत हो सकेगा। 30 1992 का 15
- (3) इस धारा के अधीन निपटारे के प्रयोजन के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रक्रिया लागू होगी। 1992 का 15
- (4) इस धारा के अधीन बोर्ड या न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध धारा 23क के अधीन कोई अपील नहीं होगी।”। 35
- नई धारा 19झख का अंतःस्थापन। 51. इस प्रकार अंतःस्थापित की गई, मूल अधिनियम की धारा 19झक के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-
- रकमों की वसूली। “19झख. (1) यदि कोई व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति के संदाय में असफल रहता है या धारा 19 के अधीन जारी प्रत्यर्पण आदेश के निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है या बोर्ड को देय किन्हीं फीसों का संदाय करने में असफल रहता है तो वसूली अधिकारी, व्यक्ति से देय रकम विनिर्दिष्ट करते हुए, विनिर्दिष्ट प्ररूप में अपने लेख में एक कथन (ऐसे कथन को इस अध्याय में इसके पश्चात् प्रमाणपत्र 40

कहा गया है) तैयार कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति से प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम को निम्नलिखित एक या अधिक पद्धतियों से वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगा, अर्थात् :—

- (क) व्यक्ति की जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय ;
 (ख) व्यक्ति के बैंक खातों की कुर्की ;
 5 (ग) व्यक्ति की स्थावर संपत्ति की कुर्की और विक्रय ;
 (घ) व्यक्ति की गिरफ्तारी और कारागार में उसका निरोध ;
 (ङ) व्यक्ति की जंगम और स्थावर संपत्तियों के प्रबंध के लिए प्रापक की नियुक्ति,

और इस प्रयोजन के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 220 से धारा 227, धारा 228क, धारा 229, धारा 232, दूसरी और तीसरी अनुसूचियों तथा समय-समय पर प्रवृत्त आय-कर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के उपबंध, जहां तक हो सके ऐसे आवश्यक उपांतरणों के साथ लागू हो सकेंगे मानो उक्त उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियम, इस अधिनियम के उपबंध थे और इस अधिनियम के अधीन देय रकम के प्रति, आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन आय-कर के स्थान पर निर्देश हैं ।

15 **स्पष्टीकरण 1**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन में, ऐसी कोई संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन सम्मिलित हैं, जो ऐसी तारीख को या उसके पश्चात्, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, अंतरित किए गए हैं, जब प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट कोई रकम, व्यक्ति द्वारा पर्याप्त प्रतिफल से भिन्न उसके पति या पत्नी या अप्राप्तवय बालक या पुत्र की पत्नी या पुत्र के अप्राप्तवय बालक को देय हो चुकी थी और जो पूर्वोक्त किन्हीं व्यक्तियों द्वारा धारित की गई है या उनके नाम पर है और जहां तक उसके अप्राप्तवय बालक या उसके पुत्र के अप्राप्तवय बालक को इस प्रकार अंतरित जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन का संबंध है वहां उसका, यथास्थिति, ऐसे अप्राप्तवय बालक या पुत्र के अप्राप्तवय बालक के वयस्क होने की तारीख के पश्चात् भी इस अध्यादेश के अधीन व्यक्ति से देय किसी रकम की वसूली करने के लिए व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन में सम्मिलित होना बना रहेगा ।

1961 का 43 **स्पष्टीकरण 2**—आय-कर अधिनियम, 1961 की दूसरी और तीसरी अनुसूचियों और आय-कर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के उपबंधों के अधीन निर्धारिती के प्रति किसी निर्देश का, प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के बारे में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके प्रति निर्देश है ।

1961 का 43 **स्पष्टीकरण 3**—आय-कर अधिनियम, 1961 के अध्याय 17घ और दूसरी अनुसूची में अपील के प्रति निर्देश का, इस अधिनियम की धारा 23क के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण के समक्ष अपील के बारे में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके प्रति निर्देश है ।

35 (2) वसूली अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय स्थानीय जिला प्रशासन की सहायता प्राप्त करने के लिए सशक्त होगा ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, धारा 19 के अधीन बोर्ड द्वारा जारी किसी निदेश के अननुपालन के अनुसरण में उपधारा (1) के अधीन किसी वसूली अधिकारी द्वारा रकमों की वसूली की, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी अन्य दावे पर अग्रता होगी ।

40 (4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए “वसूली अधिकारी” पद से बोर्ड का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसको लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाए ।

धारा 22 का संशोधन।

52. मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

नई धारा 22ग, धारा 22घ, धारा 22ङ, धारा 22च, और धारा 22छ का अंतःस्थापन।

53. मूल अधिनियम की धारा 22ख के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

विशेष न्यायालयों की स्थापना किया जाना।

“22ग. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का शीघ्र विचारण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा, उतने विशेष न्यायालयों को, जितने आवश्यक हों, स्थापित या नामनिर्दिष्ट कर सकेगी। 5

(2) विशेष न्यायालय, ऐसे एकल न्यायाधीश से गठित होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, जिसकी अधिकारिता के भीतर नियुक्त किया जाने वाला न्यायाधीश कार्यरत है, नियुक्त किया जाएगा।

(3) कोई व्यक्ति किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक वह ऐसी नियुक्ति से ठीक पूर्व, यथास्थिति, कोई सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश के पद को धारण नहीं करता है। 10

विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराध।

22घ. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व या ऐसे प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् किए गए इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का, ऐसे क्षेत्र के लिए, जिसमें अपराध किया गया है, स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा या जहां ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय हैं, उनमें से ऐसे किसी एक द्वारा, जो इस निमित्त संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, संज्ञान लिया जाएगा और विचारण किया जाएगा। 15 1974 का 2

अपील और पुनरीक्षण।

22ङ. उच्च न्यायालय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 29 और अध्याय 30 द्वारा, उच्च न्यायालय को प्रदत्त सभी शक्तियों का, जहां तक लागू हो सकें, उसी प्रकार प्रयोग कर सकेगा मानो उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों का विचारण करने वाला कोई सेशन न्यायालय था। 20 1974 का 2

विशेष न्यायालयों के समक्ष कार्यवाहियों में संहिता का लागू होना।

22च. (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय का, सेशन न्यायालय होना समझा जाएगा तथा विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति का, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खंड (प) के अर्थात्तर्गत लोक अभियोजक होना समझा जाएगा। 25 1974 का 2

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति को, सात वर्ष से अन्यून के लिए अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय में होना चाहिए या विधि के विशेष ज्ञान की अपेक्षा करते हुए संघ या राज्य के अधीन सात वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए किसी पद को धारण करना चाहिए। 30

संक्रमणकालीन उपबंध।

22छ. इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का, जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है, जब तक विशेष न्यायालय स्थापित न किया जाए, तब तक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाले सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और विचारण किया जाएगा : 35 1974 का 2

परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, इस धारा के अधीन सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए गए किसी मामले या मामलों के वर्ग को अंतरित करने के लिए संहिता की धारा 407 के अधीन उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगी।” 40

54. मूल अधिनियम की धारा 23क की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

धारा 23क का संशोधन ।

55. मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

धारा 25 का संशोधन ।

5 “(ज) धारा 19इक की उपधारा (2) के अधीन कार्यवाहियों के निपटारे के लिए बोर्ड द्वारा अवधारित निबंधन ; और

“(झ) कोई अन्य विषय जिनको विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या जिनको विनिर्दिष्ट किया जाए या जिनके संबंध में उपबंध, विनियमों द्वारा बनाया जाना है ।” ।

56. मूल अधिनियम की धारा 30 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

नई धारा 30क का अंतःस्थापन ।

10 “30क. प्रशासनिक तथा सिविल कार्यवाहियों के निपटान के संबंध में मूल अधिनियम के अधीन किया गया या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्य या कोई बात, सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य और प्रभावी समझी जाएगी मानो मूल अधिनियम में किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त थे ।” ।

कतिपय अधिनियमों का विधिमान्यकरण ।

2014 का अध्यादेश सं. 2 15

57. इस तथ्य के होते हुए भी कि प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014 प्रवर्तन में नहीं रह गया है, उक्त अध्यादेश के उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी मानो ऐसे उपबंध सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त थे ।

विधिमान्यकरण और व्यावृत्ति ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) प्रतिभूति बाजार में विनिधानकर्ताओं के हितों का संरक्षण करने, प्रतिभूति बाजार के विकास का संवर्धन और विनियमन करने के उद्देश्य से, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (बोर्ड) की स्थापना के लिए तथा उससे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियमित किया गया था।

2. प्रतिभूति बाजार की प्रकृति और ऐसी परिस्थिति, जिसमें यह प्रवृत्त होता है, गतिशील है और उसको शासित करने वाली विधियों को बाजार आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाना पड़ेगा। बोर्ड के माध्यम से प्रतिभूति बाजार के शासन ने समय की चुनौतियों का सामना किया है जिसके अंतर्गत न्यायिक संवीक्षा भी है। तथापि, वर्षों के अनुभव पर आधारित प्रतिभूति बाजार से संबंधित विधियों के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करते समय प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए विनियमात्मक उपबंधों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

3. विनिधानकर्ताओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए और प्रतिभूति बाजारों के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियों को बढ़ाना आवश्यक हो गया है—(क) न केवल प्रतिभूति बाजार से जुड़े लोगों और इकाइयों से बल्कि ऐसे व्यक्तियों से भी जो प्रतिभूति बाजार से सीधे रूप से जुड़े नहीं हैं, जानकारी मांगना; (ख) ऐसे मामलों में जहां विनिधानकर्ताओं से प्राप्त धन का कपटपूर्वक दुरुपयोग किया गया है वहां विनिधानकर्ताओं के प्रभावी संरक्षण के लिए उपबंध करना; और (ग) सामूहिक विनिधान स्कीम को मानीटर करना और यह सुनिश्चित करना कि ऐसी स्कीमों में जो भोले-भाले विनिधानकर्ताओं के व्यय पर सफल हो रही हैं उनको नियंत्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त मामलों के अधिक लंबन की दृष्टि से शीघ्र विचारण का उपबंध करने के लिए प्रतिभूति विधियों के अधीन अपराधों के अभियोजन के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया जाना आवश्यक है।

4. चूंकि संसद सत्र में नहीं थी और राष्ट्रपति का यह समाधान हो गया था कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में आवश्यक संशोधनों को करने के लिए बोर्ड को समर्थ बनाया जा सके और प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 तथा प्रतिभूति विधि (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2013 के अधीन की गई कार्रवाइयों को विधिमान्य करने के लिए राष्ट्रपति ने, 28 मार्च, 2014 को प्रतिभूति विधि संशोधन अध्यादेश, 2014 प्रख्यापित किया था। चूंकि प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014, 18 जुलाई 2014 से प्रवर्तन में नहीं रह गया है और पूर्वतर अध्यादेशों तथा प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014 के उपबंधों को सतत प्रभाव देना आवश्यक था, अतः प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 को संसद में पुरःस्थापित करना आवश्यक हो गया है।

5. प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 जो अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, अर्थात्:—

(क) किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित किसी बैंक या कोई अन्य प्राधिकरण या बोर्ड या निगम सहित, किसी व्यक्ति से ऐसी सूचना और अभिलेख मंगाने के लिए, जो बोर्ड की राय में ऐसी प्रतिभूतियों में किसी संव्यवहार की बाबत बोर्ड द्वारा किसी अन्वेषण या जांच के लिए सुसंगत होगा, बोर्ड को सशक्त करते हुए सेबी अधिनियम की धारा 11 का संशोधन करना;

(ख) सेबी अधिनियम की धारा 11 की नई उपधारा (5) में यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित करना कि, यथास्थिति, इस अधिनियम की धारा 11ख के अधीन या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 12क या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19 के अधीन जारी निदेश के अनुसरण में प्रत्यर्पित रकम को, बोर्ड द्वारा स्थापित विनिधानकर्ता संरक्षण और शिक्षा निधि में जमा किया जाएगा;

(ग) सेबी अधिनियम की धारा 11कक का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करना कि किसी स्कीम या ठहराव के अधीन निधियों का पूल किया जाना, जो बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है या इस धारा के अधीन समाविष्ट नहीं है, जिसमें एक सौ करोड़ रुपए या अधिक की समग्र रकम अंतर्वलित है, सामूहिक विनिधान स्कीम होना समझा जाएगा;

(घ) सेबी अधिनियम की धारा 11ग की उपधारा (8), उपधारा (9) और उपधारा (10) का संशोधन करना जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थान पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले मुंबई में नामनिर्दिष्ट न्यायालय के मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश को बहियों, रजिस्ट्रों, अन्य दस्तावेजों और अभिलेखों के अभिग्रहण के लिए कोई आदेश जारी करने की अधिकारिता होगी;

(ङ) सेबी अधिनियम की धारा 15क से 15जख का संशोधन करना जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धनीय शास्तियां अधिरोपित करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारियों को उक्त अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए न्यूनतम शास्तियां, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होंगी, अधिरोपित करने का विवेकाधिकार होगा;

(च) सेबी अधिनियम की धारा 15झ का संशोधन करना जिससे बोर्ड को, न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति की मात्रा में वृद्धि की जा सके यदि बोर्ड की राय में आदेश गलत है और प्रतिभूति बाजार के हित में नहीं है;

(छ) सेबी अधिनियम में नई धारा 15जख का अंतःस्थापन करना जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कोई कार्यवाहियां, धारा 11, धारा 11ख, धारा 11घ, धारा 12 या धारा 15झ के अधीन आरंभ की गई हैं, कार्यवाहियों के निपटाने के लिए बोर्ड के समक्ष आवेदन कर सकेगा जो सेबी अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संचालित किया जाएगा;

(ज) सेबी अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए "विशेष न्यायालयों" की स्थापना करना;

(झ) नई धारा 28 क का अंतःस्थापन करना जिससे ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जो धन के प्रतिदाय के लिए बोर्ड के किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है या धारा 11ख के अधीन जारी प्रत्यार्पण आदेश के किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है या बोर्ड को देय किन्हीं फीसों का संदाय करने में असफल रहता है, धन की वसूली करने के लिए वसूली अधिकारी को सशक्त किया जा सके।

6. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 में किए गए संशोधनों के समान आधारों पर प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में कतिपय संशोधन करना भी आवश्यक हो गया है।

7. विधेयक उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है।

नई दिल्ली;
31 जुलाई, 2014.

अरुण जेटली

खंडों पर टिप्पण

खंड 2—यह खंड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के कृत्यों से संबंधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम, 1992) की धारा 11 का संशोधन करता है। यह भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड को ऐसी प्रतिभूतियों जिनमें उक्त बोर्ड द्वारा अन्वेषण या जांच की आवश्यकता होती है, में किन्हीं संव्यवहार के संबंध में किसी व्यक्ति से जानकारी और अवलेख मंगाने के लिए समर्थ करने हेतु उक्त धारा की उपधारा (2) में खंड (i) का संशोधन करना प्रस्तावित करता है। यह 6 मार्च, 1998 से उक्त धारा की उपधारा (2) में खंड (ix) को अंतःस्थापित करने के लिए प्रस्तावित करता है जिससे प्रतिभूतियों के संबंध में उल्लंघन के लिए निवारण, निरोध, कार्यान्वयन और अन्वेषण से संबंधित विषयों में बोर्ड के समरूप कृत्यों को करने वाले अन्य विनियामक जो भारत के बाहर हैं, से जानकारी अभिप्राप्त करने या प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड को स्पष्ट रूप से सशक्त किया जा सके। तथापि, भारत के बाहर किसी प्राधिकरण को कोई जानकारी देने के प्रयोजन के लिए एक समझौता ज्ञापन को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से बोर्ड और विदेशी विनियामकों के मद्दे हस्ताक्षरित होगा। उक्त धारा में नई उपधारा (5) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया है जो यह उपबंध करती है कि, यथास्थिति, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 11ख या धारा 12क या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19 के अधीन जारी निदेश के अनुसरण में प्रत्यर्पित रकम को, बोर्ड द्वारा स्थापित विनिधानकर्ता संरक्षण और शिक्षा निधि में जमा किया जाएगा।

खंड 3—यह खंड, सामूहिक विनिधान स्कीमों के विनियम से संबंधित सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11क का संशोधन करता है। यह उक्त खंड की उपधारा (1) में परंतुक को अंतःस्थापित करना प्रस्तावित करता है जो यह उपबंध करता है कि किसी स्कीम या ठहराव के अधीन निधियों का पूल किया जाना, जो उक्त धारा की उपधारा (3) द्वारा अपवर्जित नहीं किया गया है और जो बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है जिसमें एक सौ करोड़ रुपए या अधिक की समग्र रकम अंतर्वलित है, सामूहिक विनिधान स्कीम होना समझा जाएगा। उक्त खंड की उपधारा (2) को यह स्पष्ट करते हुए संशोधित करना और प्रस्तावित किया गया है कि किसी स्कीम या किसी व्यक्ति द्वारा किया गया ठहराव सामूहिक विनिधान स्कीम के अधीन आएगा। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार विनिर्दिष्ट की जाने वाली शर्तों का समाधान करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई या प्रस्थापित की गई कोई स्कीम या ठहराव। उक्त खंड में उपधारा (2क) को अंतःस्थापित करना प्रस्तावित किया गया है जिससे सामूहिक विनिधान स्कीम को गठित करने संबंधी अतिरिक्त स्वतंत्र मानदंडों को विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करने के लिए बोर्ड को सशक्त किया जा सके। उक्त खंड की उपधारा (3) में नए खंड (ix) को अंतःस्थापित करना भी प्रस्तावित किया गया है जिससे सामूहिक विनिधान स्कीमों की परिधि के अधीन आने से किसी स्कीम या ठहराव को, बोर्ड के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा अपवर्जित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त किया जा सके। उपधारा (1) में अंतःस्थापित किए गए समझे जाने वाले उपबंधों की दृष्टि से यह सुनिश्चित करना प्रस्तावित किया गया है कि ऐसे धन पूल किए जाने वाले क्रियाकलाप, जिनको अन्यथा कुछ अन्य प्राधिकरण या विनियामकों द्वारा विनियमित किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विनियामक रूप से परस्पर व्याप्त नहीं हैं, सामूहिक विनिधान स्कीमों की परिधि के अधीन नहीं आते हैं।

खंड 4—यह खंड, निदेश जारी करने की शक्ति से संबंधित सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11ख का संशोधन करता है। उक्त खंड में यह स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण का अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित करता है कि बोर्ड के पास इस धारा के अधीन प्रत्यर्पित आदेशों को जारी करने की शक्ति थी और सदैव उसका होना समझा जाएगा।

खंड 5— यह खंड अन्वेषण से संबंधित सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11ग का संशोधन करने के लिए है। यह उक्त धारा 11ग की उपधारा (8), उपधारा (9) और उपधारा (10) का संशोधन करने का, यह उपबंध करने के लिए प्रस्ताव करता है कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थान पर केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित मुंबई में नामनिर्दिष्ट न्यायालय के मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश को बहियों, रजिस्ट्रों, अन्य दस्तावेजों और अभिलेख के अभिग्रहण के लिए कोई आदेश जारी करने के लिए अधिकारिता होगी।

खंड 6—यह खंड सेबी अधिनियम की धारा 15क का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धनीय शास्तियां अधिरोपित करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारियों को जानकारी, विवरणी, आदि